(b) Under 'Operation Black Board' scheme, the Government of India has provided assistance of Rs. 846.91 lakhs during 1991-92 and Rs. 1819.00 lakhs during 1992-93 (anticipated) to the State of Madhya Pradesh. Further, Central Government has provided funds to the State of Madhya Pradesh under following Centrally-sponsored schemes during 1991-92 and 1992-93 as Central assistance :

(Rs. in lakhs)

Programme	1991-92	1992-93
(i) National Malaria Eradication Programme	928.36	1203.15
(ii) National Leprosy Eradication Programme	208.62	199.00
(iii) National T.B. Control Programme	33.79	96.91
(iv) Natioal Programme for Control of Blindness.	198.95	146.76

(c) and (d) As may be seen from figures of expenditure in part (a) of the Question, the Government of Madhya Pradesh has spent almost all the amount earmarked during 1992-93.

उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि का विकास

3254. **श्री राम करेश यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में "बंजर भूमि का विकास" करने हेतु जिलावार कौन-कौन से क्षेत्र चुने गए हैं ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंजर भूमि का विकास करने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रोजगार उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकारों को धनराशि का दिया जाना

@3255. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को प्रत्येक विकास खंड में 5 लाख रुपए की दर पर 1752 विकास खंडों में वितरण करने हेतु धनराशि जारी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि यह धनराशि खर्च करके कितने कर्मकारों को रोजगार मिलने की संभावना है और उनमें से प्रत्येक को एक वर्ष में कितने दिन काम मिलने का अनुमान है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान देश में पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले 1752 खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने केन्द्रीय अंश के रूप में राज्य सरकारों को 5 लाख रुपए प्रति खंड के हिसाब से रिलीज किए हैं । वर्ष 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल किए खण्डों की संख्या और अब तक रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिए) ।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2430, 20-12-1993 से स्थानांतरित ।